राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 58 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया

जयपुर, 7 मार्च (का.सं.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से 6400 करोड़ रुपए की 58 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत प्रदेश में भी 62.58 करोड़ रुपये की लागत के तीन प्रमुख आध्यात्मिक स्थानों पर हुए विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ किया गया। इस राशि से सांवलिया सेठ मंदिर में विकास कार्य तथा करणी माता मंदिर एवं केशोरायपाटन में आध्यात्मिक अनुभव केन्द्र के विकास कार्य कराए गए हैं।

- **62.58 करोड़ रूपए के प्रदेश के 3 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के विकास कार्य भी शामिल।**

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि, इन योजनाओं से देश में पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने "देखो अपना देश पीपुल्स च्वाइस अभियान" का शुभारंभ करते हुए कहा कि, इस अभियान का उद्देश्य विदेश में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से अपील की कि, वे अपने विदेशी मित्रों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न स्थानों को वैडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा दिया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ें। श्री मोदी ने "वोकल फोर लोकल" पर जोर देते हुए देशवासियों से आ ान किया कि कहीं भी घूमने जाएं तो स्थानीय उत्पाद अवश्य खरीदें।

इस अवसर पर मंडफिया (चित्तौड़गढ़), केशोरायपाटन (बूंदी) तथा बीकानेर में आयोजित समारोहों को वर्चुअल रूप से सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि, सनातन धर्म, सभ्यता और सांस्कृतिक परम्परा का पूरी दुनिया में फिर से मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुरातन आध्यात्मिक स्थलों का पुनरूद्धार भी हो रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 20 मन्दिरों और आस्था धामों के विकास कार्यों के लिए आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

जूट की एम.एस.पी. में करीब 5.5 फीसदी की बढ़ोतरी

नयी दिल्ली,7 मार्च (वार्ता)। सरकार ने वर्ष 2024 - 25 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 285 रुपए बढ़ाकर 5335 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय की प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कच्चे जूट का एमएसपी (टीडीएन-3 पहले के टीडी-5 ग्रेड के बराबर) वर्ष 2024-25 सीज़न के लिए 5,335 रुपए रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

इससे उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत पर 64.8 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित होगा है।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है।

'मेरे प्रदेश के परिवार को नहीं होगी पानी की कमी'

मुख्यमंत्री भजन लाल ने यह भी कहा कि, पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए जारी रहेंगे भागीरथी प्रयास, प्रत्येक जल परियोजना को समय पर पूरा करेंगे

जयपुर, 7 मार्च (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि, राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में जल की महत्ता अमृत से कम नहीं है। इसी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए और आमजन को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार मिशन मोड पर कार्य कर रही है। प्रदेश के प्रत्येक गांव-ढाणी और कस्बे को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने गुरूवार को कृषि उपज मंडी समिति, बूंदी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 76.69 करोड़ रूपए की लागत से रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना (विस्तार चंबल भीलवाड़ा परियोजना) का वर्चुअल लोकार्पण किया। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की प्यास बुझाने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर गंभीरता से प्रयास कर रही है।

- **रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद् परियोजना का लोकार्पण।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को कृषि उपज मंडी समिति, बूंदी, में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 76.69 करोड़ रूपए की लागत से रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद् परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। आज जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बूंदी के 35 गांव और 47 ढाणियों को हर घर नल की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि बूंदी जिले में 68 हजार घरों को वर्तमान में पानी की आपूर्ति की जा रही है और जिले के 74 गांवों में नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी तरह से भीलवाड़ा में भी शहर के 2 लाख घरों तक पानी पहुंचाया गया है और भीलवाड़ा के 88 गांवों को शत-प्रतिशत नल से जल उपलब्ध हो चुका है। शर्मा ने कहा कि रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना के अन्तर्गत 9 हजार 227 घरेलु कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। इस परियोजना से 97 हजार से अधिक आबादी लाभान्वित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती कालीसिंध चम्बल परियोजना के मुख्य घटक नवनेरा बैराज का कार्य एक महीने में पूरा कर इसमें जल संग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा। नवनेरा बैराज के पूर्ण होने पर संशोधित पार्वती कालीसिंध परियोजना का कार्य धरातल पर शुरू हो जाएगा। कोटा एवं बूंदी जिले के 6 शहरी क्षेत्रों एवं 750 गांवां को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया है। इसके लिए लगभग 11 हजार 200 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, एवं जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कांग्रेस सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्नाटक की जनता की आस्था और विश्वास का सम्मान नहीं करते हैं। वे अराजकता, भ्रम एवं ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। वे सनातन धर्म का आदर सम्मान नहीं करते, जिसमें हम विश्वास करते हैं और वो ऐसे लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के विरूद्ध है जो हमारी आस्था के खिलाफ है। वे ऐसा करके असमंजस की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और वो ऐसा सनातन धर्म के खिलाफ कर रहे हैं जिनकी हम भर्त्सना करते हैं और हम कांग्रेस सरकार को बेनकाब करेंगे और जागरूकता उत्पन्न करेंगे, हम (सिलेबस) पाठ्यक्रम का सख्ती से विरोध करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बदलाव शामिल नहीं हो।" गत वर्ष जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी थी स्कूल की टैक्सट पुस्तकों, जो संशोधन किए गए थे उन्हें समिति ने मान लिया था। परन्तु इसको लेकर सूत्रों का कहना है कि पुनरीक्षण समिति ने तय किया था कि टीपू सुलतान से संबंधित पाठ्य सामग्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए और इस सामग्री को यथावत् रहने दिया गया।

सी.बी.आई. ने राजस्थान व महाराष्ट्र के सात शहरों में 67 स्थानों पर रेड की

820 करोड़ रुपए के संदिग्ध आई.एम.पी.एस. लेनदेन के मामले में यूको बैंक द्वारा 21 नवम्बर को की गई शिकायत के संबंध में यह कार्यवाही की गई है

जयपुर, 7 मार्च। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यूको बैंक के कई खातों से लगभग 820 करोड़ रु. के संदिग्ध आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) लेनदेन से संबंधित मामले में राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में 67 स्थानों पर छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया। राजस्थान में सीबीआई ने जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर व फलौदी में सर्च की कार्रवाई की।

सीबीआई ने यूको बैंक से प्राप्त शिकायत के आधार पर 21 नवम्बर 2023 को मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि 10 नवम्बर 2023 से 13 नवम्बर 2023 के बीच सात निजी बैंकों के लगभग 14,600 खाताधारकों से शुरू किए गए आईएमपीएस आवक लेनदेन को 41 हजार से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में गलत तरीके से भेजा गया था। इसके परिणाम स्वरूप 820 करोड़ रुपए मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना ही यूको बैंक खातों में जमा हुए। कई खाताधारकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया और विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन निकालकर गलत लाभ कमाया। इससे पूर्व, दिसंबर 2023 में कोलकाता व मैंगलोर में निजी व्यक्तियों तथा यूको बैंक के अधिकारियों से जुड़े 13 स्थानों पर तलाशी ली गई।

- **राजस्थान में सी.बी.आई. ने जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर व फलौदी में तलाशी अभियान चलाया।**
- **कार्रवाई के दौरान यूको बैंक और आई.डी.एफ.सी. से आपत्तिजनक दस्तावेज़, 43 डिजिटल डिवाइस जब्त किए।**

इस दौरान बुधवार को को प्रदेश के जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर, फलौदी सहित में तलाश अभियान चलाया गया। साथ ही महाराष्ट्र के पुणे में भी छापेमारी कर तलाशी ली गई। इस बीच यूको बैंक और आईडीएफसी से संबंधित लगभग 130 आपत्तिजनक दस्तावेज़, साथ ही डिजिटल डिवाइस के रुप में 40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क तथा 1 इंटरनेट डोंगल फोरेंसिक जांच के लिए जब्त किए गए।

एस.बी.आई. के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक इलैक्टोरल बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए उसे 30 जून तक का वक्त चाहिए।

ए.डी.आर. का तर्क है कि एस.बी.आई. ने जानबूझकर अंतिम क्षणों में 4 मार्च 2024 को आवेदन पेश किया, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आगामी लोकसभा चुनावों से पूर्व दानदाताओं और दान की राशि का ब्यौरा सार्वजनिक ना हो। वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में अब तक की गई प्रगति के बारे में भी नहीं बताना चाहता। यहां तक कि वह थोड़ी बहुत अनुपालना का भी खुलासा नहीं करना चाहता।

याचिकाकर्ता ने ध्यान दिलाया है कि एस.बी.आई. के आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र में उसके चेयरमैन या प्रबंध निदेशक की ओर से शपथ नहीं ली गई है, बल्कि एस.बी.आई. के एक छोटे पदाधिकारी किसी नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा शपथ ली गई है जो स्वयं को एस.बी.आई., मुम्बई के कॉरपोरेट सैन्टर में सहायक महाप्रबंधक बताते हैं।

याचिका में कहा गया है कि "यह आश्चर्यजनक है कि एस.बी.आई. की वैबसाइट में मुम्बई के कॉरपोरेट सैक्टर में कार्यरत जिन 59 हाईरैंकिंग ऑफिसर्स की लिस्ट है, उसमें नरेन्द्र प्रताप सिंह का नाम कि नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि "एस.बी.आई. के पास प्रत्येक आवंटित इलैक्टोरल बॉन्ड और उसके क्रेता की के.वाई.सी. डिटेल्स है। ई.बी. स्कीम के सैक्शन 4 में ही के.वाई.सी. की जरूरत के बारे में बताया होता है, इसलिए एस.बी.आई. प्रत्येक इलैक्टोरल बॉन्ड के क्रेता की पहचान के बारे में भली-भांति जानता है। यह मानने वाली बात नहीं है कि एस.बी.आई. के डेटा बेस में संग्रहित जानकारी बिल्कुल तैयार स्थिति में नहीं है।"

ए.डी.आर. ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 15 मार्च 2019 के अपने शपथ पत्र में कहा था कि इस स्कीम में मान्य के.वाई.सी. और ऑडिट ट्रेल के साथ बॉन्ड्स खरीदने के एक पारदर्शी सिस्टम की परिकल्पना की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा बाद में यह भी स्वीकार किया गया था कि दानदाता के के.वाई.सी. दस्तावेज, पैन नम्बर, उसकी पहचान और पूर्ण पते का एस.बी.आई. द्वारा रिकॉर्ड रखा जाता है।"

याचिका में कहा गया है कि विशेषज्ञों के अनुसार "चूंकि प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक बॉन्ड का एक अलग ही यूनिक नम्बर होता है, इसलिए डेटा बेस पर साधारण सर्च करने पर ही एक विशेष फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, जिसके लिए किसी मैन्युअल वैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सीलबंद लिफाफे एक चैक की भांति केवल भौतिक साधन हैं, जबकि चैक जमा कराए जाने का वास्तविक ट्रांजैक्शन डेटा बेस में होता जिसे सॉफ्टवेयर पर सर्च करने में आसानी से जनरेट किया जा सकता है।"

याचिका में कहा गया कि एक आर.टी.आई. पूछताछ से पता चला कि एस.बी.आई. ने बॉन्ड्स के प्रबंधन के लिए आई.टी. सिस्टम डवलपमैन्ट पर 60 लाख 43 हजार 5 रूपए व्यय किए थे, ऑपरेशनल लागत 89 लाख 72 हजार 338 रूपए थी और इलैक्टोरल बॉन्ड्स को अस्तित्व में लाने की शुद्ध लागत 1 करोड़ 50 लाख 15 हजार 338 रूपए आयी। इसका मतलब है कि इलैक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री और उनसे प्राप्त नकदी के प्रबंधन के लिए सुनियोजित आई.टी. सिस्टम पहले से ही मौजूद है।

- **परोक्ष रूप से एस.बी.आई. पर आरोप लगाया गया है कि, एस.बी.आई. जानबूझ कर तीस जून तक का समय मांग रही है, क्योंकि तीस जून से पहले तो लोकसभा के चुनाव पूरे हो चुके होंगे तथा वोटर के पास में यह जानकारी कि, किस कम्पनी ने कितने इलैक्टोरल बॉण्ड किस पार्टी को दिये, मतदान होने बाद पहुंचेगी।**
- **याचिका में यह भी उल्लिखित है कि, एस.बी.आई. ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जानकारी प्रदान करने के लिये समयावधि पूर्ण होने के एक दिन पहले ही याचिका दी, जिससे जानकारी चाहने वाले के पास, जानकारी प्राप्त करने का कोई विकल्प न बचे।**

याचिका में उल्लेख किया गया है कि एस.बी.आई. की 29 प्राधिकृत शाखाओं में से 19 ने ही इलैक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री की और एस.बी.आई. की 14 शाखाओं में उन्हें भुनाया गया। जनवरी 2024 को उपलब्ध डेटा से यह भी पता चलता है कि सिर्फ 25 राजनीतिक दलों ने ही अपने खाते खुलवाए थे और वे ही इलैक्टोरल बॉन्ड्स के नकदीकरण के पात्र हैं। इसलिए इस जानकारी को संकलित करना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए पहले से ही सिस्टम मौजूद है।

एस.एम.एस. अस्पताल के डॉक्टर रंजन लाम्बा के ठिकानों पर ए.सी.बी. का छापा

आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में ए.सी.बी. की टीमों ने डॉ. रंजन लाम्बा के जयपुर, झुंझुनूं और सीकर स्थित घर और अस्पताल पर तलाशी ली

जयपुर, 7 मार्च। एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) की टीमों ने गुरुवार सुबह सवाई मानसिंह अस्पताल (एस.एम.एस.) के डॉक्टर रंजन लांबा के जयपुर, झुंझुनूं और सीकर स्थित घर और अस्पताल पर छापेमारी की कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार ए.सी.बी. को एस.एम.एस. अस्पताल में सर्जरी यूनिट-8 के चिकित्साधिकारी डॉ. रंजन लाम्बा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली थी। इस पर ए.सी.बी. से जांच करवाई गई। इस दौरान ए.सी.बी. को कई संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली। डॉ. लांबा के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट से अनुमति लेकर रेड की गई।

- **आरोपी डॉक्टर ने अपनी पत्नी एवं रिश्तेदारों के नाम से जयपुर और आसपास आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों, फ्लैट और म्युचअल फण्ड व इंश्योरेंस में निवेश कर रखा है।**
- **ए.सी.बी. ने आरोपी एवं उसके परिजनों के नाम से विभिन्न स्थानों पर करीब 22 आवासीय एवं कृषि भूखण्डों के करोड़ों रूपए कीमत के दस्तावेज बरामद किए थे।**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि डॉ. लांबा के जयपुर के चित्रकूट स्थित आवास और एक अन्य ठिकाने पर ए.सी.बी. की टीमों ने अलसुबह सर्च अभियान चलाया। साथ ही झुंझुनूं में उसके निजी हॉस्पिटल और आवास पर और सीकर में फ्लैट और आवास पर तलाशी ली गई।

ए.सी.बी. के पुलिस निरीक्षक रघुवीर शर्मा ने बताया कि डॉ. लांबा ने एस.एम.एस. अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित की है। सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। इसकी जांच करने के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं।

ब्यूरो की एफ.आई.आर. और अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी डॉक्टर ने अपनी पत्नी एवं रिश्तेदारों के नाम से अनेक परिसम्पत्तियां ली है। यह उसकी वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक है। आरोपी चिकित्साधिकारी ने अपनी अवैध आय को जयपुर शहर एवं आसपास में आवासीय, व्यावसायिक, भूखण्डों, फ्लैटों और म्यूचअल फण्ड, इन्श्योरेन्स आदि में निवेश कर रखा था। आरोपी एवं उसके परिजनों के नाम से विभिन्न स्थानों पर करीब 22 आवासीय एवं कृषि भूखण्डों के दस्तावेज बरामद हुये हैं। कीमत करोड़ों रुपयों की मानी जा रही है। आरोपी और उसके परिजनों के कई बैंक खाते मिले हैं।

उप महानिरीक्षक कालूराम रावत के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी जारी है।

सैन्ट्रल इलैक्शन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दी है।

तमिलनाडू की कुल 39 सीटों में से कांग्रेस 9 सीटों पर और पुडुचेरी की सीट पर भी चुनाव लड़ेगी।

कई राज्यों में तो कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर चुनाव लड़ने में उसे ऐड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा।

- **जहां तक इन सीटों सीटों की संख्या का सवाल है, जहां कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस की स्थिति सुखद नहीं बल्कि गंभीर लग रही है।**

कर्नाटक और तेलंगाना से प्राप्त नवीनतम खबरें कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साहजनक नहीं है।

यू.पी.ए. के द्वितीय कार्यकाल, यानी कि वर्ष 2009 में कांग्रेस ने 440 सीटों पर चुनाव लउत्रा था और 206 सीटों पर विजय प्राप्त की थी।

वर्ष 2014 में कांग्रेस ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 44 सीटें ही जीत सकी और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थीं।

कुछ बड़े राज्यों में चुनावी गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस के लिए स्थिति विकट बनी हुई है।

केन्द्रीय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से यह 50 प्रतिशत हो गया है। इसके मद्देनजर अब आवास भत्ते के साथ ही ग्रेच्युटी आदि में भी बढोतरी होगी।

वायनाड सीट से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फिर हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है। अटकलें तेज हो गई हैं कि 2024 में भी इस सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं।

पहली बार ममता ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया तथा फिर उनको उठाकर बस में ठूंस दिया गया। प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों, जो कि एक बस में विवादित स्थल की तरफ जा रहे थे, को हिरासत में ले लिया गया जिससे वे आगे न जा सकें।

पहले से अलग, विडंबना थी कि, इस बार उन्हें राज्य पुलिस द्वारा संरक्षित इलाके में ही आयोजन करना पड़ा तथा वहीं राज्य पुलिस विरोधियों का दामन कर रही थी। इस घटनाक्रम ने उनके प्रति बढ़ती अवज्ञा का संकेत दिया।

उसी समय पर, वह सी.बी.आई. की एक टीम को संदेशखाली के उन स्थानों पर जाने से नहीं रोक पाई, जहां ई.डी. टीम को शेख शाहजहां से पूछताछ के लिए उनके घर जाते समय तृणमूल के गुंडों ने पीटा।

पर इस बार सी.बी.आई. टीम वहां गई और राज्य पुलिस को अपनी ताकत का अहसास कराया, जो उनका पूर्व में सहयोगी नहीं कर रही थी।

सी.बी.आई. टीम, संदेशखाली में उस विशाल शेख शाहजहां बाजार के आस-पास भी गई, जहां मुख्य अभियुक्त का कार्यालय था। यह बाजार, ग्रामीण से हड़पी हुई जमीन पर बनाया गया था।

इस पूरे घटनाक्रम ने, तृणमूल नेता के सर्वशक्तिमान होने के खोखले दावे की पोल खोल दी। ममता बनर्जी संदेशखाली के आसपास भी नहीं थी जबकि जिन ताकतों को उन्होंने संदेशखाली से दूर रखने की कोशिश की थी, वहीं ताकतें (सी.बी.आई. और ई.डी.) उन स्थानों का खुले आम से दौरा कर रहीं थी।

सी.बी.आई. की एक टीम ने, अभियुक्त के घर के पास ही एक अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता के घर का दौरा किया जहां ई.डी. अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। शंकर आध्या के घर पर, 12 जनवरी को, ई.डी. टीम के साथ धक्का-मुक्की की गई थी।

- **सी.बी.आई. की टीम भी बेधड़क संदेशखाली में, उसी जगह घूम-घूम कर जानकारियां व सबूत इकट्ठे कर रही है, जहां तृणमूल के कार्यकर्ताओं व शेख शाहजहां के समर्थकों ने सी.बी.आई. को आगे बढ़ने से रोका था तथा उनके साथ मार-पिटाई भी की थी।**
- **आज के इस घटनाक्रम ने उस किंवदंती का खोखलापन भी उजागर किया कि, बंगाल सर्वशक्तिशाली ममता बनर्जी का इलाका है, जहां वो ही हो सकता है, जो ममता चाहती हैं।**

आपकी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई है: राहुल गांधी

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बांसवाड़ा पहुंची, विशाल जनसभा आयोजित

बांसवाड़ा, 7 मार्च (निसं)। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि, आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई है और इसके लिये कानून भी बनाये जायेंगे। राहुल गाँधी, बांसवाड़ा जिले में पहुँची भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

राहुल गांधी ने कहा कि, देश को सिर्फ पांच प्रतिशत लोग चला रहे हैं ऐसे में कांग्रेस सरकार आयी तो सबसे पहले 30 लाख सरकारी पद जो खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार इन पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि, युवाओं को प्रशिक्षण का अधिकार कानूनी रुप में दिया जायेगा ताकि स्नातक या डिप्लोमा होल्डर होते ही युवाओं को एक साल का प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने कहा कि, इसमें निजी क्षेत्र के साथ ही सरकारी दफ्तरों को भी शामिल किया जायेगा। एक साल तक के इस प्रशिक्षण में एक लाख रुपया भी दिया जायेगा। इसी तरह पेपरलीक जैसे मामलों को लेकर कड़ा कानून बनाया जायेगा और किंग केटरर्स, ओला, होम डिलिवरी जैसे कार्य करने वालों को भी सामाजिक सुरक्षा और पेंशन दी जायेगी।

- **सचिन पायलट ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, राहुल जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और आम जनता उनके साथ है।**
- **जनसभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया।**

राहुल ने कहा कि, मोदी सरकार ने स्टार्टअप, स्टैण्ड अप, मेक इन इंडिया जैसे नारे दिये लेकिन इसका लाभ दो तीन अरबपतियों ने ही लिया है, ऐसे में कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक खंड की व्यवस्था की गयी है, जिससे हर जिले में 10 करोड़ रुपये का फंड रखा जायेगा जिससे गरीब, बेरोजगार, किसान भी अपना व्यवसाय शुरु कर दें। उन्होंने बताया कि, किसानों को एम.एस.पी. का लाभ मिले इसे भी कानूनी रुप दिया जायेगा। उन्होंने जातिगत आंकडे बताते हुए कहा कि, अगर हम संस्थाओं को देखें तो कहीं भी दलित, पिछड़े आदिवासी की भागीदारी नज़र नहीं आती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनका चेहरा तक नहीं दिखा। उन्होंने सवाल किया कि, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसी गरीब, किसान, मजदूर, विकलांग का चेहरा दिखाई नहीं दिया। अगर वहां कोई चेहरे थे तो वे अडानी, अंबानी और बॉलीवुड की लाईन थी तथा केवल उद्योगपति और अरबपति ही नजर आ रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अंबेडकर और नेहरू की बदौलत आज लोकतंत्र जिन्दा है और हमें अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने सभा को सफल करार देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम को भी सराहा। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर राहुल यात्रा निकाल रहे हैं उनमें आम जनता उनके साथ है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कार्यकर्ता चुनौतियों का मुकाबला हौसले के साथ करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुटता का परिचय देते हुए विरोधियों को चुनौती देनी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि आदिवासियों के डीएनए में और कण-कण में कांग्रेस समायी हुई है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908